फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 300 प्रभात जयपुर, बुधवार 3 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

She Was Superb
She Was Suman Kalyanpur

'Tumne pukaara aur hum chale aaye' (Rajkumar, 1964), 'Dil ek mandir hai' (Dil Ek Mandir, 1963), 'Ajahoon na aaye baalma' (Saanjh Aur Savera, 1964), 'Dil ne phir yaad kiya' (Dil Ne Phir Yaad Kiya, 1966)

Does Honey Really Never Expire?

टीएमसी में नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह फैलता ही जा रहा है

विद्रोहियों का कहना है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 उनके साथ हैं, अगर यह दावा सही है तो ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी का गुट पार्टी के प्रतीक चिन्हों का उपयोग भी नहीं कर पाएगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। तृणमूल कांग्रेस में बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत तब हुई, जब पार्टी के दो विधायकों ने विपक्ष के नेता के चुनाव में उनके जाली हस्ताक्षर इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कोलकाता नगर निगम के पार्षद तारक सिंह ने आज अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग की। उनके इस्तीफे के गहरे राजनीतिक मायने हैं।

ताज़ा आकलन के अनुसार, बागी गुट का दावा है कि नव-निर्वाचित 80 विधायकों में से कम से कम 50 उनके साथ हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो ममता बनर्जी-अभिषेक बनर्जी गुट शायद पार्टी का चुनाव चिह्न भी खो सकता है।

चुने हुए असंतुष्ट जनप्रतिनिधियों की लगातार अलग-अलग बैठकें हो रही हैं। तृणमूल के सदस्य अब खुलकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश आलोचकों का मानना है कि चुनावी हार की मुख्य जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी पर है।

- टीएमसी के भ्रष्टाचार की भी नित नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार टीएमसी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉलेजों व कॉलेज यूनियनों में भी फैला है। यहाँ हर साल एडमीशन के समय करोड़ों की हेराफेरी होती थी।
- सुरेन्द्रनाथ कॉलेज के छात्र संघ ऑफिस में भारी मात्रा में नकदी मिली है। इस यूनियन पर छात्र नेता देबाशीष बनर्जी (देबू कनकटा) का कब्जा था, कॉलेज के सभी मामलों पर उसी का नियंत्रण था। वो सुदीप बंदोपाध्याय व उनकी पत्नी का करीबी बताया जाता है। उसके कमरे से दो लगेज ट्रॉली में नोट भरे हुए मिले हैं, जिनमें से अधिकांश को दीमक खा गई है। इनमें पुराने नोट भी हैं।
- इस छात्रसंघ ऑफिस से सटे दो पूर्ण सुसज्जित बैडरूम भी मिले हैं, जिन्हें किराए पर दिया जाता था।
- कालना के पूर्व टीएमसी विधायक के महल जैसे आवास से एक चुराई गई एम्बुलैंस भी मिली है।

ये बागी विधायक अब वर्षों की चुप्पी के बाद अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वे पहले क्यों नहीं बोले, तो उनका एक ही जवाब होता है कि पिछली व्यवस्था में असहमति जताना संभव नहीं था। उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा था।

मौजूदा स्थिति में पार्टी पूरे बंगाल में बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तृणमूल कार्यकर्ताओं तथा पंचायत प्रधानों, नगर पार्षदों और यहां तक कि विधायकों को भी खदेड़ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में तृणमूल के दफ्तरों की ओर दौड़ लगा रहे हैं और वहां से लगातार नई-नई चीजें बरामद हो रही हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंदी की मौत पर विरोधाभासी रिपोर्ट

जयपुर, 2 जून। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई बंदी की मौत के मामले में पुलिस की ओर से विरोधाभासी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने पर आईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने आईओ से पूछा है कि जब पूर्व आईओ ने मामले में आरोपियों का जुर्म प्रमाणित मान लिया है तो फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अनुसंधान जारी होना क्यों बताया है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता रामप्रकाश कुमावत ने बताया कि परिवादी रामस्वरूप कुमावत ने अपने भाई सुनील की पुलिस हिरासत में हुई मौत की रिपोर्ट 2022 में एसएमएस पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर सीआईडी सीबी ने तीन पुलिसकर्मियों व तीन निजी व्यक्तियों को मृतक बंदी की हत्या का दोषी मान लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को गिरफ्तार करने व निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए

- अदालत ने कहा, जब पूर्व आईओ ने जुर्म प्रमाणित मान लिया तो आईओ ने रिपोर्ट में अनुसंधान जारी होना कैसे बताया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते'

इज़रायल के बेरुत पर भीषण हमले से नाराज़ ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर खूब खरी-खोटी सुनाई

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। इज़रायल द्वारा बेरुत पर हमलों को रोकने से इनकार करने से नाराज़ अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि "अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते।" यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका ईरान के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए युद्धविराम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। इससे अमेरिका व इज़रायल में मतभेद उजागर हो गए है।

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बेरुत पर योजनाबद्ध हमले को रद्द करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत तनावपूर्ण हो गई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर सैन्य कार्यवाही को लेकर इज़रायली नेता को खरी-खोटी सुनाई।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि बातचीत के बाद नेतन्याहू ने अपना रुख बदल दिया और हिज़बुल्लाह के प्रतिनिधियों ने भी इज़रायल पर हमले रोकने पर सहमति जताई, जिससे इज़रायल-लेबनान सीमा पर तनाव कम होने की उम्मीद जगी।

ट्रंप ने कहा, "आज (सोमवार) मेरी बिबी नेतन्याहू से बातचीत हुई, जिसमें मैंने उनसे कहा कि बेरुत पर बड़ा हमला न करें, और उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस मोड़ दिया। धन्यवाद बिबी," ट्रंप अक्सर इज़रायली प्रधानमंत्री के लोकप्रिय उपनाम का इस्तेमाल करते है।

ट्रंप की नेतन्याहू से फोन कॉल की बात उस समय आई, जब ईरान ने इज़रायल के लेबनान पर हमलों के कारण अमेरिका के साथ वार्ता समाप्त करने की धमकी दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हिज़बुल्लाह इज़रायल पर

- एक अमेरिकन मीडिया कंपनी एक्सियोस ने अनाम अमेरिकन अफसर के हवाले से ट्रंप व इज़रायल के प्र.मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई तीखी बातचीत की जानकारी दी। फोन पर बातचीत के दौरान, लेबनान पर इज़रायल के हमले पर भारी नाराज़गी जताई और नेतन्याहू से कहा कि तुमसे सब नफरत करते हैं और तुम्हारी वजह से इज़रायल से।
- समझा जाता है कि लेबनान पर इज़रायल के हमले के बाद ईरान ने शांति वार्ता से हटने के संकेत दिए थे, इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। हालांकि, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि एक-दूसरे पर हमला रोकने के लिए मान गए हैं, पर कुछ अमेरिकन अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर असल बात उजागर की।
- अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का यह कथित गुस्सा अमेरिका के लोगों को यह दिखाने का चतुर मीडिया दांव है कि सब कुछ उनके काबू में है या वास्तव में वे नेतन्याहू पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिद्धारमैया 2028 तक सीएम हाउस में ही रहेंगे

समझा जाता है कि नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को सरकारी मुख्यमंत्री आवास "कावेरी" में रहने की सहमति दी है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 जून। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बीच एक अनोखी आवास व्यवस्था सामने आई है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया पद छोड़कर, डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता बना रहे हैं, लेकिन परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री को आवंटित किए जाने वाले आधिकारिक आवास 'कावेरी' के उपयोग में कोई बदलाव नहीं होगा।

सूत्रों के अनुसार, दोनों शीर्ष नेताओं ने आधिकारिक आवास को लेकर आपसी सहमति से एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वर्ष 2028 तक औपचारिक रूप से कावेरी बंगले को अपने पास रखेंगे और वहीं निवास करते रहेंगे।

इसके परिणामस्वरूप, नए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार शुरूआत में अपने निजी आवास से ही कामकाज करेंगे और वहीं रहेंगे। बाद में वे किसी अन्य उपयुक्त सरकारी आवास को अपना आधिकारिक निवास बनाएंगे, बजाय इसके कि वे पारंपरिक मुख्यमंत्री आवास में जाएँ।

लंबे इंतजार के बाद, डी.के. शिवकुमार 3 जून को लोक भवन में राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शिवकुमार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण

- शिवकुमार नए सरकारी भवन से अपना कामकाज करेंगे। ज्ञातव्य है कि वे 3 जून को शपथ लेंगे, जिसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा।
- डीके शिवकुमार ने कहा, शपथ ग्रहण सादा समारोह में होगा, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों को लाने के लिए 17,000 से ज्यादा वाहन बुक किए गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोखंडे सीताराम सीबीएसई के चेयरमैन, भारद्वाज सचिव नियुक्त

नई दिल्ली, 02 जून। बाहरवीं के छात्रों की ऑन-स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर विवादों में घिरी सीबीएसई के खिलाफ सरकार मंगलवार को एक्शन में दिखी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यही नहीं, आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़े टेंडर मामले की जांच के लिए भी एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसका जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान

- ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर से जुड़े विवाद की जांच कैपेसिटी बिल्डिंग कॉरपोरेशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा में भी छाया राजनैतिक वंशवाद

पार्टी के नेताओं की अपनी संतानों को चुनाव लड़ाने की महत्वाकांक्षा ने नेतृत्व को त्रस्त कर दिया है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 जून। राजनैतिक परिवारवाद के कारण भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिए दर्जनों स्थापित नेताओं के बच्चे टिकट के लिए कतार में हैं।

संख्या के मामले में कांग्रेस की तुलना में भाजपा में वंशवादी राजनीतिज्ञ कम हैं, लेकिन सत्ता में व्यापक उपस्थिति के कारण, इसके पास वास्तविक संख्या काफी ज्यादा है। वर्तमान में, कुल मिलाकर 5204 सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों में से 21 प्रतिशत सदस्य राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिसमें 31 प्रतिशत कांग्रेस से और लगभग 18 प्रतिशत भाजपा से हैं, जैसा कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं। भाजपा ने अन्य पार्टियों के राजनैतिक परिवारों को भी अपने साथ जोड़ा है (जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया) और अपने ही नेताओं के परिवारों को आगे बढ़ाया है (अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, पूनम महाजन, दुष्यंत सिंह आदि)। हालांकि, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वंशवादी नहीं है।

हाल के वर्षों में, राजनीतिक उत्तराधिकारियों की महत्वाकांक्षाएँ स्पष्ट रूप से बढ़ गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े पुत्र पंकज यूपी विधानसभा में विधायक हैं। बताया जाता है कि अब उनके छोटे बेटे नीरज लखनऊ ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव ने 2024 के चुनावों में गाज़ीपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी; अब वे विधानसभा के लिए वही सीट हासिल करने में जुटे हैं। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के पुत्र करण महाराजपुर में

- एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया कि कुल 5204 मौजूदा सांसदों, विधायकों में से 21 प्रतिशत राजनैतिक परिवारों से हैं। इनमें से 31 प्रतिशत कांग्रेस के हैं और 18 प्रतिशत भाजपा से हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने कुछ राजनैतिक परिवार कांग्रेस से ग्रहण किए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ को उसने खुद पाला-पोसा है, जिनमें राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, दुष्यंत सिंह, पूनम महाजन, बृजभूषण शरण सिंह आदि प्रमुख हैं।
- राजनाथ सिंह के बड़े पुत्र पंकज पहले से विधायक हैं और अब छोटे पुत्र नीरज भी मैदान में कूद पड़े हैं। जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा विधायक है, दूसरा सांसद है और अब वे अपनी बेटी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
- ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है, जो अपने बच्चों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।

पेपर लीक आरोपी को आगामी नीट परीक्षा के लिए पुस्तकें मिलेंगी

नई दिल्ली, 02 जून। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के एक आरोपी को आगामी नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने इस मामले के पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ ाने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाले नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी। पेशी के दौरान यश

- अदालत ने 21 जून की परीक्षा के लिए यह अनुमति दी तथा न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत में ब्लू कॉलर वर्कर्स (नलवाला, बिजली वाला, खाती आदि) की भारी कमी आ सकती है

कैनडा की मैक्रो ट्रैड्ंस रिसर्च फर्म "पाइन ट्री" के संस्थापक रितेश जैन ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्लू कॉलर वर्कर्स की भारी मांग है, जिसकी आपूर्ति वे भारत से कर रहे हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। यह चेतावनी कैनडा की एक मैक्रो ट्रेंड्स रिसर्च फर्म, पाइनट्री के संस्थापक रितेश जैन ने दी है। उनका कहना है कि विकसित देशों में बढ़ते जनसांख्यिकीय संकट के कारण वैश्विक श्रम बाजार में एक नया रुझान उभर रहा है, जिसमें भारतीय ब्लू-कॉलर (शारीरिक श्रम करने वाले) कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ेगी।

जैन का मानना है कि अगले पांच वर्षों में भारत में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, ड्राइवर, नर्स और देखभाल करने वालों (केयर गिवर्स) की कमी हो सकती है, क्योंकि अमीर देश उन श्रमिकों की आक्रामक तरीके से भर्ती करेंगे, जिनकी उन्हें अपने यहां कमी पड़ रही है।

उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "दुनिया में ब्लू-कॉलर श्रमिकों की कमी है और वाइट-कॉलर (दफ्ततरी काम करने वाले) कर्मचारियों की अधिकता है।" उनके अनुसार, यह वैश्विक श्रम बाजार में उभर रहा सबसे बड़ा असंतुलन है।

- जैन ने बताया कि दुनिया में भारी "लेबर मार्केट" असंतुलन पैदा हो रहा है। यूरोप व विश्व के अन्य विकसित देशों की आबादी कम हो रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, खाती, नर्स, ड्राइवर जैसे कुशल कामगारों की संख्या घटी है और इसका जवाब इन देशों ने भारत में ढूंढा है, जहाँ से बड़ी तादात में कुशल कामगार आयात किए जा रहे हैं।
- जैन ने कहा, विडम्बना यह है कि विश्व में कुशल कामगारों की मांग बढ़ी है, पर भारत में बेरोजगार स्नातकों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक सर्वे में पता चला है कि उच्च शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी, कम शिक्षित युवा वर्ग की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब यूरोप और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी होती आबादी, घटती जन्म दर और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बनी हुई श्रमिकों की कमी से जूझ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, 1970 के दशक के बाद से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी दुनिया भर में लगभग दोगुनी हो चुकी है और 2070 के दशक तक इसके फिर से लगभग दोगुना होने की संभावना है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का अनुमान है कि अब दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे देशों में रहती है, जहां जन्म दर जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट के 5 नये न्यायाधीशों ने शपथ ली

नई दिल्ली, 02 जून। सुप्रीम कोर्ट के पांच नवनियुक्त जजों ने मंगलवार को अपने पद की शपथ ली, जिससे कोर्ट अपनी स्वीकृत संख्या 38 जजों तक पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट वी. मोहना को शपथ दिलाई। केन्द्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 22 मई और 27 मई को हुई बैठकों में की गई सिफारिशों के बाद इनकी नियुक्तियों को अधिसूचित किया था।

नए नियुक्त लोगों में हाई कोर्ट के चार मौजूदा मुख्य न्यायाधीश शामिल

- अब सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत संख्या सभी 38 स्थान भर गये हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)